THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): (a) Yes, Sir. The following literature was published and sent to overseas offices for publicity:

(1) A portfolio titled 'The India of Gandhi'.

(2) A folder printed by the Gujarat Tourism Development Corporation on Gandhi and places connected with his life.

(3) A number of existing brochures/directories covering places associated with Gandhiji.

(b) The response has been substantial, particularly due to the interest generated by the screening of the film 'Gandhi'.

Evaluation of suitable aircraft for Air India

204. SHRI M. BASAVARAJU: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether the Sub-Committee of the Board of Directors of Air India which was constituted sometime back to evaluate various types of aircraft available in the market and recommend the most suitable aircraft for introduction into the fleet of Air India has submitted its report;

(b) if so, what are the details thereof and what action has been taken thereon; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, by when the report is likely to be submitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Committee on the basis of offers available at that time recommended the acquisition of B767-200-ER aircraft but observed that there was considerable scope for negotiating the price and other terms and conditions with the two competitors viz. Boeing and Airbus Industries. Negotiations were accordingly held to obtain the best offers. The Air India Board taking into account the revised offers decided to acquire six A310-300 aircraft on operational and financial considerations.

(c) Does not arise in view of the reply given to (a) above.

वाराणसी छावनी से होकर कुछ गांवों के लिए वैकल्पिक मार्ग

205. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी छावनी से होकर कुमाहर पुरवा, सरइया और फुलवारियां गांवों को जाने के लिए जो वैकल्पिक मार्ग दिये जाने का प्रस्ताव था, उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक आरम्भ किया जायेगा और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है और अब तक कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) कार्य की प्रवृत्ति को देखते हुये इसके वर्षाकाल के पश्चात ही आरम्भ होने की सम्भावना है । आशा है कि कार्य के आरम्भ होने पर सडक और पुलिया का निर्माण कार्य इस कार्य के शुरू होने से छः महीने के अन्दर और पुल का निर्माण डेढ़ वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

(ग) वाराणसी छावनी बोर्ड द्वारा तैयार किये गये अनुमानों और सक्षम

एम० ई० एस० प्रधिकारियों द्वारा तकनीकी रूप से मंजूर इस परियोजना पर लागत 17,08,978 रुपये की आयेगी। यह धनराशि सरकार द्वारा फरवरी 1984 में पहले ही मंजूर कर दी गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी का प्रचार

206. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के न तो अध्यक्ष हो और न प्रबन्ध निदेशक हो हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेते हैं जिससे इन बैंकों में हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रसार में बाधा पड रही है;

(ख) क्या यह सच है कि भाग 'क' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में तथा अधिसूचित कार्यालयों में जहां मूल काम मात्र हिन्दी में ही किया जाना चाहिये, हिन्दी में यह काम अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी):

(क) चूंकि 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं इसलिए वे समिति की बैठकों में भाग नही लेते। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के सदस्य है और उनकी अनुपस्थिति में बैंक के उप गवर्नर/कार्यपालक निदेशक बैठक में भाग लेते है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार इस समिति की सदस्य संख्या 30 तक ही सीमित है। बैंकों के अध्यक्षों को इस समिति का सदस्य बना दिए जाने से समिति का संचालन करना सहज नही रहैगा।

प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की क्षेत्र/मंडल/अंचल और प्रधान कार्यालय स्तरों पर अपनी-अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां होती हैं जिनकी अध्यक्षता सम्बद्ध कार्यालयो के प्रमुख करते हैं। इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं जिनमें राजभाषा के प्रयोग के संबंध में समीक्षा की जाती है और काम मे सुधार करने के लिए सुझाव दिए जाते है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों और 1983-85 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार बैंकों से "क" क्षेत्र मे 66.7 प्रतिशत तक मूल पत्राचार हिन्दी में करने के लिए कहा गया है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन शाखाएं अधिसूचित करने के अलावा कुछ बैंकों ने अपनी कुछ ऐसी ग्रामीण शाखाओं का भी चयन किया है जहां सारा काम हिन्दी मे ही किया जाना है।

इस संबंध मे बैंकों के काम पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही रिपोर्टों के जरिए बराबर नजर रखी जाती है और जब कभी कोई त्रुटि दिखाई देती है तब संबंधित बैंक के अध्यक्ष को उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाता है।

Vayudoot service in different places of Maharashtra

207. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) what is the progress so far made in starting the Vayudoot ser-